



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67268

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10870 सन् 2026

भूपेंद्र सिंह

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता :-अनवर हुसैन, अविनाश मणि त्रिपाठी, सुनील कुमार चौधरी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री अनवर हुसैन, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा श्री शिव दत्त शुक्ला, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 32 सन् 2026, धारा 319(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4, 11, 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024, थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर के अधीन विचाराधीन मुकदमे में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 26.2.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता तथा 2024 के अध्यादेश के अंतर्गत अपराधों के लिए दर्ज की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक सत्यम के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4 दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक सत्यम के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया गया और वह 26.2.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह आरोपित है कि जिस अध्यादेश के अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, वह पहले ही निरस्त किया जा चुका है और दिनांक 15.7.2024 को अधिनियम प्रख्यापित किया गया है।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करने के उपरांत एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **भूपेंद्र सिंह** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए रु. 50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लाएगा / उन्हें आतंकित नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अभिलिखित करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

अभिषेक